(क) दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार देश के विभि न्यायालयों में हिन्दू विवाह अधिनियम और महिलाओं के शोषज से संबंधित कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान और महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम. थम्बी दुरई): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

124. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के संबंध में सरकार का क्या विचार है;

(ख) न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर पाये गये मतभेद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में ऊंचे स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम. थम्बी दुरई): (क) शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची की मदों में से एक मद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने और न्याय पालिका के लिए एक आचरण संहिता तैयार करने के लिए, एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना है।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती है। सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी स्तर पर मत वैभिनय या हस्तक्षेप की जानकारी नहीं है।

Recommendations of the high powered committee on electoral funding

125. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the recommendations of the high prowered committee on electroal funding;

(b) what is Government's reaction thereto; and

(c) the steps taken to create an election fund for funding of election for candidates of recognised parties?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) to (c) A statement containing the gist of recommendations made by the Committee on State Funding of Elections is laid on the Table of the House. (*see* below) The recommendations of the Committee would be discussed with political parties.

Statement

Gist of Recommendations of Committee on State Funding of Elections

1. **State Funding of Elections :**

The Committee has recommended, to begin with, only partial State assistance, in kind only in the form of certain facilities, to recognised polictical parties in way that it provides them relief not only in carrying out their electoral activities and meeting partly the cost of essential items of electioneering campaigns of their candidates, but also helps them partially in the current administration of their day to day functioning during non-election period. Gradually, more and more of their expenses' burden can be progressively shifted to the State so that ultimately all their legitimate expenses become a charge on the State. In this respect, the Committee has recommended creation of a separate Eleciton Fund to which the Central Government may contribute at the rate of Rs. 10/- per elector *i.e.* about Rs. 600 crores annually. The State Governments also, all taken together, may contribute proportionately Rs. 600 crores annually to the Fund.

In its report, the Committee has also specified the nature of facilities to be provided to the recognised political parties and their candidates at State cost. These incldue:—

(I) For Recognised Political Parties:

(i) Suitable rent-free accommodation for its headquarter.

(ii) One rent-free telephone, with STD facility with a specified number of telephone calls over and above the free calls permitted to any subscriber.